THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Wednesday, 03 Dec, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 2 : Social Justice / Prelims**	डब्ल्यूएचओ वजन घटाने के लिए जीएलपी -1 दवाओं के उपयोग का समर्थन करता है
Page 07 **Syllabus : GS 3 : Environment / Prelims**	अमेरिका के धक्का-मुक्की के बीच संयुक्त राष्ट्र की जलवायु रिपोर्ट पर काम कर रहे विशेषज्ञ
Page 07 **Syllabus : GS 1 : Geography / Prelims**	कोसी नदी का बदलता मार्ग तटबंधों के खतरों को कैसे उजागर करता है
Page 08 **Syllabus : GS 2 & 3 : Governance and Internal security / Prelims**	जीरो स्टार्स : साइबर अपराध से निपटने के लिए संचार साथी ऐप को अनिवार्य करना एक ओवरकिल है
Page 10 Syllabus : GS 2 : IR	यूक्रेन में शांति क्यों नहीं है?
Page 08 : Editorial Analysis **Syllabus : GS-2: IR**	हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग के लिए एक खाका

Page 01 : GS 2 : Social Justice / Prelims

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने वयस्कों में दीर्घकालिक मोटापे के प्रबंधन के लिए जीएलपी -1 (ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड -1) एगोनिस्ट दवाओं के उपयोग पर अपना पहला वैश्विक दिशानिर्देश जारी किया है। ये दिशानिर्देश ऐसे समय में आए हैं जब मोटापा एक वैश्विक महामारी बन गया है, जिसके बड़े स्वास्थ्य और आर्थिक परिणाम हैं। डब्ल्यूएचओ का रुख एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव को चिह्नित करता है, जो इन दवाओं की प्रभावशीलता और गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) से लड़ने में समान पहुंच की आवश्यकता दोनों को स्वीकार करता है।

WHO backs use of GLP-1 drugs for weight loss

Ramya Kannan
CHENNAI

In a much-anticipated development, the World Health Organization (WHO) has finally issued global guidelines on the use of popular weight loss drugs. These glucagon-like peptide-1 (GLP-1) therapies are being used for the treatment of obesity in adults.

The WHO guidelines released on December 1 posit equitable access as the key element of using such therapies, and read them as one element of a full complement of actions against obesity.

"While medication alone won't solve this global health crisis, GLP-1 therapies can help millions overcome obesity and reduce its associated harms," WHO director general Tedros Adhanom Ghebreyesus said, while launching these guidelines.

With the guidelines, the WHO recognises that the GLP-1 class of drugs are indeed effective, and that they are likely to have an impact on the global costs of obesity. Beyond its health impacts, the global economic cost of obesity is predicted to reach $3 trillion annually by 2030.

There are two primary components to the WHO's recommendations: That GLP-1 therapies may be used by adults, excluding pregnant women, conditionally, for the long-term treatment of obesity; and that intensive behavioural interventions in diet and physical activity must be continued alongside the drugs.

The WHO also specified that while the efficacy of these therapies in treating obesity and improving me-

WHO guidelines posit equitable access as the key element of using such therapies.

tabolic and other outcomes was evident, it was making a conditional recommendation partly because of the limited data available on long-term efficacy, safety and probable outcomes when the drugs are discontinued, but also because of their costs which put them out of the reach of many people.

Obesity is a complex chronic disease and a major driver of non-communicable diseases, such as cardiovascular diseases, type 2 diabetes, and some types of cancer.

It also contributes to poorer outcomes for patients who have infectious diseases.

It is only in recent years that the treatment for obesity has been revolutionised by the emergence of a class of drugs that not only effect significant weight loss, but also confer a whole range of metabolic benefits to individuals.

Equitable access

A special communication in the recent issue of *JAMA* notes that "medication alone cannot solve the global obesity burden. Countries must ensure equitable access not only to comprehensive disease management, but also to health promotion and prevention policies and interventions targeting the general population and those at high risk."

Anoop Mishra, director of the National Diabetes, Obesity, and Cholesterol Foundation, said: "I believe this statement by the WHO is a progressive step towards obesity management worldwide. For India, the costs of these drugs is a roadblock that needs more efforts, insurance coverage and development of generics."

V. Mohan, chairman of the Madras Diabetes Research Foundation, added: "It is good that the WHO's guidelines specify that the drugs alone will not suffice." "Your diet and exercise are paramount, and only when those fail, and when you really need the help of a drug or if morbidly obese, then you go for these drugs," he said.

दिशानिर्देश क्यों मायने रखते हैं?

- मोटापे को अब एक पुरानी, जटिल बीमारी के रूप में पहचाना जाता है, न कि केवल एक जीवन शैली का मुद्दा।

- यह हृदय रोगों, मधुमेह, कैंसर और संक्रामक रोगों में खराब परिणामों का एक प्रमुख चालक है।
- मोटापे का वैश्विक आर्थिक बोझ 2030 तक 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- जीएलपी -1 दवाओं (जैसे सेमाग्लूटाइड) ने अपने नाटकीय वजन घटाने और चयापचय लाभों के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है।

WHO के दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं

1. जीएलपी-1 उपयोग के लिए सशर्त अनुशंसा

- जीएलपी -1 दवाओं का उपयोग वयस्कों (गर्भवती महिलाओं को छोड़कर) में मोटापे के दीर्घकालिक उपचार के लिए किया जा सकता है।
- यह एक सशर्त सिफारिश है जिसके कारण:
  - सीमित दीर्घकालिक सुरक्षा डेटा
  - बंद करने के बाद परिणामों के बारे में अनिश्चितता
  - अत्यधिक उच्च लागत पहुंच को असमान बनाती है

2. व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप आवश्यक है

- डब्ल्यूएचओ इस बात पर जोर देता है कि अकेले दवा मोटापे को हल नहीं कर सकती है।
- पर निरंतर ध्यान:
  - आहार संशोधन
  - शारीरिक गतिविधि
  - व्यवहार परामर्श

3. एक मूल सिद्धांत के रूप में इक्विटी

- दिशानिर्देश समान पहुंच पर प्रकाश डालते हैं, चेतावनी देते हैं कि उच्च कीमतें इन दवाओं को निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) के लिए दुर्गम बनाती हैं।
- मोटापा प्रबंधन को इसके साथ एकीकृत किया जाना चाहिए:
  - स्वास्थ्य संवर्धन

- रोकथाम रणनीतियाँ
- व्यापक एनसीडी नीतियां

भारत के लिए निहितार्थ

1. पहुंच और सामर्थ्य चुनौतियाँ

- डॉ. अनूप मिश्रा जैसे भारतीय विशेषज्ञ जीएलपी-1 दवाओं की उच्च लागत को एक बाधा के रूप में उजागर करते हैं।
- के लिए ज़रूरत:
  - बीमा कवरेज
  - जेनेरिक विकल्पों का विकास
  - राष्ट्रीय मोटापा और मधुमेह कार्यक्रमों में शामिल करना

2. जीवनशैली हस्तक्षेप का महत्व

- जैसा कि डॉ. वी. मोहन बताते हैं, दवाओं को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए:
  - स्वस्थ आहार
  - नियमित व्यायाम
- जीएलपी -1 की सिफारिश केवल तभी की जाती है जब जीवनशैली के उपाय विफल हो जाते हैं या गंभीर मोटापे के मामलों में।

3. मोटापे और एनसीडी का बोझ

- भारत में तेजी से विकास हो रहा है:
  - मोटापा
  - टाइप-2 डायबिटीज
  - हृदय रोग
- डब्ल्यूएचओ की सिफारिशें सरकार को अधिक संरचित मोटापा प्रबंधन नीति अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं।

समाप्ति

□□□□□ □□□□□□□

मोटापा प्रबंधन के लिए जीएलपी -1 दवाओं का डब्ल्यूएचओ का समर्थन वैश्विक स्वास्थ्य नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। जबकि ये दवाएं आशाजनक परिणाम प्रदान करती हैं, डब्ल्यूएचओ उन्हें एक स्टैंडअलोन समाधान के रूप में देखने के खिलाफ चेतावनी देता है। समान पहुंच, निरंतर जीवन शैली हस्तक्षेप और व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों पर जोर एक संतुलित, समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारत के लिए, चुनौती सामर्थ्य सुनिश्चित करने, निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और मोटापा प्रबंधन को व्यापक एनसीडी नियंत्रण कार्यक्रमों में एकीकृत करने में है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: हाल ही में समाचारों में जीएलपी -1 शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है:

(a) एक जीन-संपादन उपकरण

(बी) वजन घटाने और मधुमेह विरोधी दवाओं का एक वर्ग

(c) एक टीका सहायक

(d) एक स्टेम-सेल थेरेपी

उत्तर: b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: जीएलपी-1 उपचारों की उच्च लागत और सीमित उपलब्धता वैश्विक स्वास्थ्य असमानताओं को गहरा करने का जोखिम उठाती है। चर्चा करें कि भारत डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के अनुरूप किफायती और सुलभ मोटापे का उपचार कैसे सुनिश्चित कर सकता है। **(150 शब्द)**

Page 07 : GS 3 : Environment / Prelims

□□□□□ □□□□□□□

जैसे ही जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) पेरिस में अपनी **सातवीं आकलन रिपोर्ट (एआर 7)** पर काम शुरू करता है , जलवायु विज्ञान के आसपास के भू-राजनीतिक तनाव फिर से सामने आए हैं। मानवजनित जलवायु परिवर्तन पर मजबूत वैश्विक सहमति के बावजूद, राष्ट्रपति ट्रम्प के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बार फिर जलवायु विज्ञान की वैधता पर सवाल उठाया है, ग्लोबल वार्मिंग को "धोखा" कहा है। यह एक महत्वपूर्ण समय में आया है जब दुनिया तेजी से **1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग सीमा के** करीब पहुंच रही है, और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग कमजोर हो रहा है।

US President Trump has ordered cuts in funding for climate research. AP

Experts work on UN climate report amid U.S. pushback

Agence France Presse

Some 600 experts began work on December 1 on the next major United Nations climate report even as U.S. President Donald Trump has continued to call the science of global warming a "hoax."

French Ecological Transition Minister Monique Barbut, whose country is hosting the five-day meeting in a Paris suburb, told the scientists their "extremely precious" work is crucial as multilateralism has weakened.

"Too many people deny the results of your work," she told the experts from more than 100 countries gathered in a skyscraper in Saint Denis for the opening of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) meeting.

Their work faces hurdles in the face of a U.S. administration whose president called climate change the "greatest con job ever" during a speech at the UN in September.

One of the co-chairs of an IPCC working group is U.S. climate expert Katherine Calvin, who was fired from her job as chief scientist at NASA following cuts ordered by the Trump administration.

"The statements, for example, from the American administration on the origin of climate change, the fact that it's a hoax, if you will, we still find that quite surprising," said an official at the French ecological transition ministry who requested anonymity.

Their work has run afoul of President Trump, who called climate change the greatest con job ever, while addressing the UN

The previous IPCC report, released in 2023, had warned that the world was on track to exceed the 1.5 C warming threshold by 2030.

The UN now says that safer limit will be breached earlier than feared.

The meeting in France launches a process that will culminate with the IPCC's Seventh Assessment Report (AR7), due to be published in 2028 or 2029.

It brings together lead authors of the report in a single venue for the first time, in an effort to tackle interdisciplinary climate questions.

The IPCC operates by consensus.

"If any country opposes the text, the report cannot be approved. Every country has a sort of veto," climate scientist Robert Vautard told reporters last week.

While the U.S. government stays out of the climate fray, dozens of American scientists are among the experts working on the IPCC report.

"IPCC reports are going to continue to underpin climate policies and climate action at every level, including international negotiations," IPCC chairman Jim Skea told the gathering.

There already appear to be disagreements over the timing of the next report's publication.

A group called the High Ambition Coalition, which includes European Union countries and developing nations vulnerable to climate change, wants the assessment to come out in 2028.

That would coincide with the global stocktake, a review, required under the Paris Agreement, of the progress countries have made in limiting climate change and its impacts.

But a group of emerging economies and major fossil fuel producing countries say more time is needed and are advocating for 2029.

The divide echoes the disagreements seen at the recent COP30 climate summit in Brazil, which concluded with a deal that left out an explicit call to phase out fossil fuels.

Despite the disagreements over when to publish the next report, Mr. Skea had said in March: "I don't think the IPCC is in crisis. We will resolve this issue about the timeline."

समाचार की मुख्य विशेषताएं

1. IPCC ने AR7 पर काम शुरू किया (2028-29)

- 600+ देशों के लगभग 100 विशेषज्ञों **ने AR7 का मसौदा तैयार करना शुरू करने के लिए फ्रांस में बैठक की है।**
- यह पहली बार है जब सभी प्रमुख लेखक एक स्थान पर मिल रहे हैं, जिसका उद्देश्य अंतःविषय समन्वय को मजबूत करना है।
- आम सहमति के आधार पर AR7 के **2028 या 2029** में प्रकाशित होने की उम्मीद है।

2. जलवायु विज्ञान के खिलाफ अमेरिकी पुशबैक

- राष्ट्रपति ट्रम्प ने जलवायु परिवर्तन को "अब तक का सबसे बड़ा ठग काम" कहा है।
- अमेरिकी जलवायु अनुसंधान निधि में **महत्वपूर्ण कटौती का** आदेश दिया गया है।
- अमेरिकी जलवायु वैज्ञानिक **कैथरीन केल्विन**, एक आईपीसीसी कार्य समूह के सह-अध्यक्ष, को इन कटौतियों के कारण नासा से निकाल दिया गया था।
- सरकार के रुख के बावजूद, **दर्जनों अमेरिकी वैज्ञानिक** अभी भी आईपीसीसी में योगदान दे रहे हैं।

3. बहुपक्षवाद को कमजोर करना

- फ्रांसीसी पारिस्थितिक संक्रमण मंत्री मोनिक बारबट ने जोर देकर कहा कि जलवायु विज्ञान पर हमला हो रहा है।
- आईपीसीसी आम सहमति पर काम करता है, जिसका अर्थ है कि एक देश भी रिपोर्ट के अनुमोदन को रोक सकता है।
- यह ढांचा इस प्रक्रिया को राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील बनाता है, खासकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भर देशों द्वारा।

4. बढ़ते जलवायु जोखिम तात्कालिकता को उजागर करते हैं

- पिछली आईपीसीसी रिपोर्ट (2023) ने चेतावनी दी थी कि **2030 तक दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस** से अधिक हो जाएगी।

- संयुक्त राष्ट्र अब कहता है कि पहले भी सुरक्षित सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है।
- AR7 की तात्कालिकता अधिक है, लेकिन राजनीतिक असहमति इसके कार्यक्रम को धीमा कर रही है।

5. प्रकाशन समयरेखा पर असहमति

समूह 1: उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन

(यूरोपीय संघ + जलवायु-संवेदनशील देशों सहित)

- 7 में AR2028 पेरिस समझौते के तहत **ग्लोबल स्टॉकटेक** के साथ संरेखित करना चाहते हैं।
- उद्देश्य: मजबूत प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाएं।

समूह 2: उभरती अर्थव्यवस्थाएं + जीवाश्म ईंधन उत्पादक

- 7 में AR2029 **चाहते** हैं, यह तर्क देते हुए कि अधिक समय की आवश्यकता है।
- उनकी स्थिति ब्राजील में COP30 **में देखे गए प्रतिरोध को प्रतिध्वनित करती है**, जहां देशों ने जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से परहेज किया।

समाप्ति

IPCC की AR7 प्रक्रिया की शुरुआत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हुई है जब दुनिया तेजी से अपरिवर्तनीय जलवायु सीमा के करीब पहुंच रही है। फिर भी जलवायु विज्ञान का बढ़ता राजनीतिकरण - विशेष रूप से अमेरिकी प्रशासन की बार-बार बर्खास्तगी - यह दर्शाता है कि भू-राजनीतिक तनाव वैश्विक जलवायु कार्रवाई को कैसे खतरे में डालते हैं। जबकि रिपोर्ट की समयरेखा पर असहमति उच्च महत्वाकांक्षा वाले देशों और जीवाश्म ईंधन पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं के बीच गहरे विभाजन को दर्शाती है, आईपीसीसी जलवायु वार्ता को सूचित करने के लिए केंद्रीय बना हुआ है। आगे की चुनौती यह सुनिश्चित करने में है कि वैज्ञानिक अखंडता राजनीतिक बाधा पर हावी हो, जिससे दुनिया बढ़ते जलवायु संकट पर तेजी से कार्रवाई कर सके।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. IPCC जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत एक वैज्ञानिक निकाय है।

2. आईपीसीसी सदस्य देशों की वैज्ञानिक सहमति के आधार पर आवधिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है।

3. सभी आईपीसीसी रिपोर्टों को सदस्य सरकारों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) केवल 2

उत्तर: b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : आईपीसीसी की एआर7 रिपोर्ट की रिलीज टाइमलाइन पर असहमति जलवायु-कमजोर देशों और जीवाश्म ईंधन-निर्भर अर्थव्यवस्थाओं के बीच गहरे विभाजन को दर्शाती है। परखना। **(150 शब्द)**

Page : 07 : GS 1 : Geography / Prelims

कोसी जिसे अक्सर "बिहार की दुखों की नदी" कहा जाता है - दुनिया की सबसे गतिशील और तलछट-भारी नदियों में से एक है। कोसी और अन्य पूर्वी गंगा नदियों के किनारे दशकों के तटबंध निर्माण के बावजूद, विनाशकारी बाढ़ जारी है। बहस फिर से सामने आती है: क्या तटबंध बाढ़ को नियंत्रित करते हैं या उन्हें खराब करते हैं?

THE HINDU

INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

□□□□□ □□□□□□□

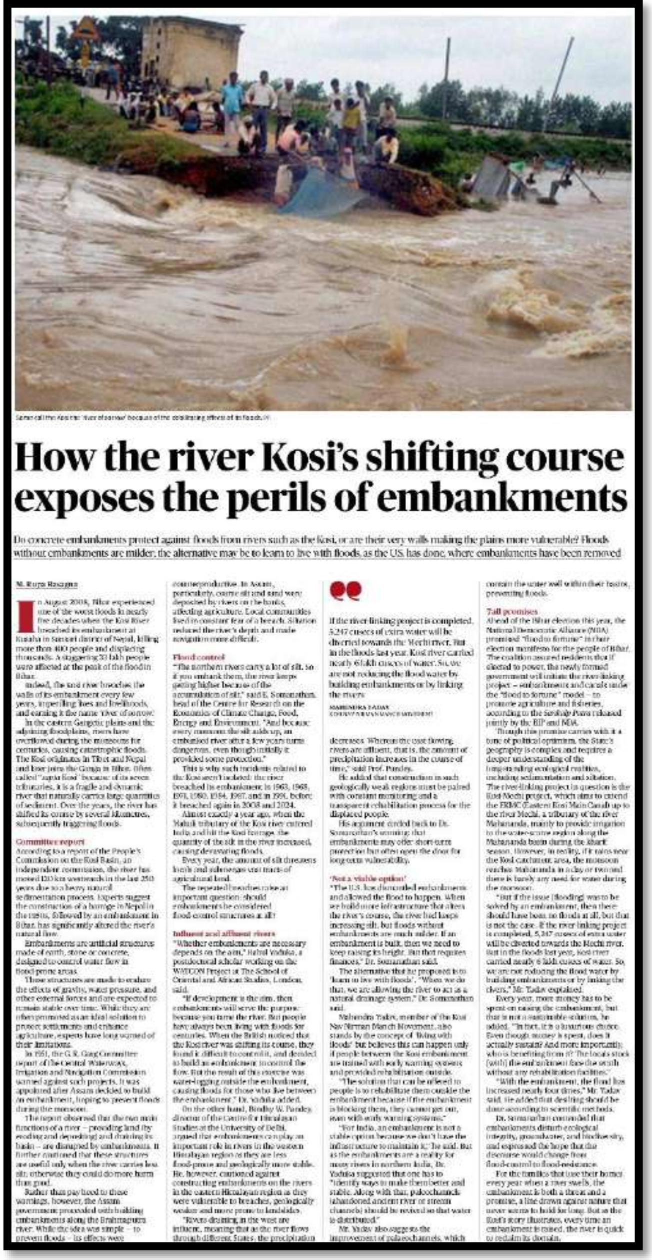

How the river Kosi's shifting course exposes the perils of embankments

Do concrete embankments protect against floods from rivers such as the Kosi, or are their very walls making the plains more vulnerable? Floods without embankments are milder; the alternative may be to learn to live with floods, as the US has done, where embankments have been removed

कोसी इतनी खतरनाक क्यों है? (भौगोलिक और जल विज्ञान कारण)

(a) उच्च अवसादन

- कोसी तिब्बत + नेपाल के युवा, नाजुक हिमालय में निकलती है → भारी तलछट भार है।

- सप्त कोसी (7 सहायक नदियों) के नाम से जाना जाता है।
- यह उच्च गाद भार हर साल नदी के तल को ऊपर उठाता है।

(b) स्थानांतरण प्रकृति

- कोसी बेसिन पर पीपुल्स कमीशन के अनुसार: कोसी 250 वर्षों में 120 किमी पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गई, जो दुनिया की सबसे अधिक प्रवासन दरों में से एक है।

(c) समृद्ध बनाम प्रभावशाली नदियाँ

- पूर्वी हिमालयी नदियाँ समृद्ध हैं → पानी नीचे की ओर बढ़ता है (मैदानी इलाकों में अधिक वर्षा)।
- पश्चिमी हिमालयी नदियाँ प्रभावित होती हैं → पानी नीचे की ओर कम हो जाता है।

यह पूर्व में तटबंधों को और अधिक असुरक्षित बनाता है।

तटबंध: रक्षा करने का इरादा है, लेकिन वे जोखिम बढ़ाते हैं

तटबंधों को क्या करना चाहिए था

- मानसून की बाढ़ को रोकें।
- कृषि, बस्तियों, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना।

लेकिन हकीकत इसके विपरीत है।

तटबंध बाढ़ को कैसे बदतर बनाते हैं (वैज्ञानिक तंत्र)

(1) गाद जमा होने से तटबंध के अंदर नदी का स्तर बढ़ जाता है

"गाद जमा होने के कारण तटबंध वाली नदी ऊंची होती जा रही है। — ई. सोमनाथन

- नदी का तल हर साल उगता है।
- कुछ वर्षों के बाद नदी विनाशकारी जोखिम → आसपास की भूमि से अधिक बहती है।

(2) उल्लंघन अपरिहार्य हो जाता है

कोसी के उल्लंघन के वर्ष: 1963, 1968, 1971, 1980, 1984, 1987, 1991, 2008, 2024

→ आवृत्ति संरचनात्मक विफलता को दर्शाती है।

(3) तटबंध के बाहर जलभराव

- तटबंधों के बीच लोग और खेत फंस गए हैं।
- जल निकासी नहीं, जिससे स्थायी जल-भराव हो जाता है।

(4) बाढ़ की तीव्रता 4 गुना अधिक हो जाती है

(कोसी कार्यकर्ताओं के अनुसार)

(5) तटबंध की ऊंचाई लगातार बढ़ाई जानी चाहिए

- भारी वित्तीय लागत
- फिर भी कभी पर्याप्त नहीं।

(6) पारिस्थितिक व्यवधान

- प्राकृतिक जल निकासी को अवरुद्ध करता है
- जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है
- भूजल पुनर्भरण को बदलता है

- बाढ़ के मैदानों को नष्ट करता है

ऐतिहासिक चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया

जीआर गर्ग समिति (1951)

चेतावनी दी कि:

- नदियों को कटाव + जमा करने की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है।
- तटबंध दोनों कार्यों को बाधित करते हैं।
- केवल कम गाद वाली नदियों के साथ सुरक्षित।

इसके बावजूद, असम और बिहार ने तटबंधों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया, विशेष रूप से:

- ब्रह्मपुत्र
- कोसी

बिना तटबंधों के बाढ़ कैसे हल्की हो जाती है

अमेरिकी उदाहरण:

- कई तटबंधों को तोड़ दिया गया है।
- बाढ़ के मैदानों को बहाल कर दिया गया।
- बाढ़ हल्की, पूर्वानुमानित और फैली हुई होती है, जिससे कम नुकसान होता है।

बाढ़ तभी खतरनाक हो जाती है जब नदियां अप्राकृतिक रूप से सीमित हो जाती हैं।

कोसी तटबंध विशेष रूप से विफल क्यों होते हैं

(क) भू-वैज्ञानिक रूप से कमजोर पूर्वी हिमालय → भूस्खलन → भारी तलछट

(ख) माहुली जैसी सहायक नदियाँ अचानक बाढ़ के → कोसी बैराज में गाद बढ़ा देती हैं

(c) बाढ़ को प्रबंधित करने के बजाय उन्हें "नियंत्रित" करने के लिए राजनीतिक दबाव

(d) खराब रखरखाव, भ्रष्टाचार, गाद निकालने की कमी

(ङ) तटबंधों के बीच फंसे लोग प्रति वर्ष सबसे अधिक हताहतों →

राजनीति और नदी-जोड़ो (कोसी-मेची परियोजना)

सरकार का "फ्लड टू फॉर्च्यून" वादा

- सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए कोसी को मेची से जोड़ा जाए।
- दावा: बाढ़ को रोकने के लिए अतिरिक्त पानी को मोड़ें।

समीक्षा:

- पिछले साल कोसी बाढ़ = 6 लाख क्यूसेक
- नहर नगण्य प्रभाव → केवल 5247 क्यूसेक का मार्ग बदल सकती है
- यदि तटबंध एक समाधान होता, तो हर साल बाढ़ नहीं आती।

मुख्य दोष:

- कोसी-महानंदा बेल्ट में बाढ़ नेपाल की तलहटी में वर्षा पर निर्भर करती है, → पानी वैसे भी 1-2 दिनों के भीतर मेची पहुंच जाता है।

विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए विकल्प

1. "बाढ़ के साथ जीना सीखो" (डॉ. सोमनाथन)
   - नदी को मुक्त रहने दें।
   - बाढ़ हल्की रहती है।
   - मौसमी कृषि के लिए बाढ़ के मैदानों का उपयोग करें।
2. तटबंधों के अंदर लोगों का पुनर्वास
   - प्रारंभिक चेतावनी + सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरण
   - वैकल्पिक भूमि, आजीविका प्रदान करें
3. पैलियोचैनल पुनर्स्थापित करें
   - प्राचीन परित्यक्त चैनल उच्च प्रवाह को अवशोषित कर सकते हैं।
   - मुख्य नदी पर दबाव कम करें।
4. वैज्ञानिक गाद निकालना
5. बाढ़-नियंत्रण पर बाढ़-लचीलापन

शिफ्ट प्रवचन:

- नदियों को नियंत्रित करने से →
- प्राकृतिक बाढ़ चक्रों के अनुकूल होने के लिए।

समाप्ति

कोसी की कहानी गलत हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक सबक है। नदी को "वश में" करने के लिए तटबंध बनाए गए थे, लेकिन इसके बजाय उनके पास है:

- बढ़ी हुई गाद
- बाढ़ की तीव्रता बढ़ गई
- फंसे हुए समुदाय
- बार-बार उल्लंघन का कारण बनता है
- गहरी भेद्यता

लेख अंततः दिखाता है: नदियों को सीमित नहीं किया जा सकता है। गंगा के मैदानों में बाढ़ को "नियंत्रित" करने की समस्या नहीं है, बल्कि इसे अपनाने के लिए एक प्राकृतिक वास्तविकता है।

कोसी बार-बार अपने बाढ़ के मैदानों को फिर से प्राप्त करती है, हमें याद दिलाती है कि तटबंध सुरक्षा नहीं बल्कि एक खतरनाक भ्रम हैं।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. कोसी नदी ने पिछले 250 वर्षों में लगभग 120 किमी पश्चिम की ओर अपना मार्ग बदल दिया है।

2. कोसी को "सप्त कोसी" के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी सात सहायक नदियाँ हैं।

3. 2008 की बाढ़ नेपाल में तटबंध टूटने के कारण आई थी।

विकल्प:

A. केवल 1 और 2

B. केवल 1 और 3

C. केवल 2 और 3

D. 1, 2 और 3

उत्तर: d)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : चर्चा कीजिए कि कोसी नदी का बदलता मार्ग पूर्वी गंगा के मैदानों में नदियों की भू-आकृति संबंधी चुनौतियों को कैसे दर्शाता है।**(250 शब्द)**

□□□□□ □□□□□□

Page 10 : GS 2 & 3 : Governance and Internal security / Prelims

बढ़ते साइबर अपराधों के जवाब में - "डिजिटल गिरफ्तारियों" से लेकर बड़े पैमाने पर सीमा पार घोटालों तक - दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दो निर्देश जारी किए हैं। एक मैसेजिंग ऐप के लिए सिम बाइंडिंग को अनिवार्य करता है, और दूसरे के लिए सभी स्मार्टफोन निर्माताओं को मार्च 2026 तक **संचार साथी** ऐप को प्री-इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है । जबकि नकली आईएमईआई नंबरों और नकली उपकरणों से जुड़ी धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने का इरादा है, इस कदम ने दखल देने वाली निगरानी, गोपनीयता उल्लंघन और राज्य की कार्रवाई की आनुपातिकता के बारे में चिंताओं को जन्म दिया है।

Zero stars

Mandating the Sanchar Saathi app to tackle cybercrime is an overkill

The growing sophistication of cybercrimes, from "digital arrests" to anonymous, large-scale cross-border scams, has made tackling them both urgent and difficult. Cybercriminals have exploited a security gap wherein user accounts on instant messaging apps remain functional even after the associated SIM card has been removed, using this anonymity to conduct government impersonation fraud. The rampant use of spoofed or tampered IMEI numbers has also made tracking perpetrators nearly impossible for law enforcement. It is perhaps inevitable that the government seeks sharper tools to address these software and hardware vulnerabilities, which explains the Department of Telecommunications' directives on November 28 and December 1. The first mandates "SIM binding" – ensuring that a user's account is disabled if the physical SIM is removed. In the second, smartphone manufacturers must pre-install the Sanchar Saathi app to verify device authenticity in all new devices by March 2026. While the first directive is a security patch which could inconvenience WhatsApp/Internet messaging users, the second is reminiscent of the saying, the road to hell is often paved with good intentions. The solution to the problem of counterfeit handsets and spoofed IMEI numbers is a cure that could potentially be more damaging than the disease.

The explicit instruction in the directive that the app is "readily visible and accessible to the end users at the time of first use or device setup and that its functionalities are not disabled or restricted" would mean that this app will be given a higher security clearance within the phone's operating system, allowing it more intrusive access to features such as camera, phone or SMS access. The potential for misuse of this app for state surveillance and being utilised by a malicious entity after compromise to target millions of users is very present and clear. This is no empty fear considering what the Union government has done with the use of Pegasus software to target the political opposition, journalists and activists. Notwithstanding Union Minister Jyotiraditya Scindia's clarification that users could delete the app, the directive's text mandating that it cannot be disabled suggests that it will function more as a Panopticon and less as a simple verification tool. As the Supreme Court's K.S. Puttaswamy (2017) judgment established, any state intrusion into privacy must satisfy the tests of legality, necessity, and proportionality. The government already possesses less intrusive means to verify device genuineness. The Sanchar Saathi web portals, SMS-based checks, and USSD codes should suffice. By ignoring these less invasive alternatives, the directive on Sanchar Saathi fails the proportionality standard. It is little wonder that privacy-conscious manufacturers such as Apple have reportedly refused to comply with this order.

पृष्ठभूमि: बढ़ते साइबर अपराध जोखिम

भारत ने देखा है:

- मैसेजिंग ऐप के माध्यम से बढ़ती सरकारी प्रतिरूपण धोखाधड़ी।
- नकली आईएमईआई नंबरों **का दुरुपयोग**, कानून प्रवर्तन में बाधा डालना।
- "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटाले और सीमा पार आपराधिक नेटवर्क।

सरकार का तर्क है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पारिस्थितिकी तंत्र में इन कमजोरियों को दूर करने के लिए मजबूत उपकरण आवश्यक हैं।

दूरसंचार विभाग के निर्देशों के प्रमुख तत्व

1. सिम बाइंडिंग

- सिम कार्ड को भौतिक रूप से निकालने पर मैसेजिंग खाते अक्षम कर दिए जाएंगे।
- यह साइबर धोखाधड़ी में गुमनामी की खामियों को दूर करता है।
- हालाँकि, यह सभी डिवाइसों में WhatsApp जैसे ऐप्स के वैध उपयोग को बाधित कर सकता है।

2. संचार साथी की अनिवार्य पूर्व-स्थापना

- सभी नए स्मार्टफ़ोन को ऐप के साथ शिप करना होगा।
- यह दृश्यमान होना चाहिए**, पहले उपयोग में सुलभ होना चाहिए**, और **इसे अक्षम नहीं किया जा सकता है**।
- ऐप में डिवाइस प्रमाणीकरण के लिए उच्च-स्तरीय सिस्टम अनुमतियाँ होंगी।

इसकी आलोचना क्यों की जा रही है

1. दखल देने वाली प्रणाली-स्तरीय पहुंच

अनिवार्य ऐप को निम्न के लिए उन्नत अनुमतियाँ प्राप्त हो सकती हैं:

- एक्सेस कैमरा
- फोन/एसएमएस फ़ंक्शन एक्सेस करें

- पृष्ठभूमि में लगातार चलाएं

यह जोखिम का विस्तार करता है:

- **राज्य निगरानी**, या
- **दुर्भावनापूर्ण शोषण** यदि ऐप से समझौता किया जाता है।

2. पिछली मिसालें अविश्वास बढ़ाती हैं

चिंताएँ निम्न से उत्पन्न होती हैं:

- पेगासस स्पाइवेयर का दस्तावेजी दुरुपयोग
- पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और विपक्षी सदस्यों की निगरानी के उदाहरण

यह ऐतिहासिक संदर्भ गोपनीयता घुसपैठ की आशंकाओं को बढ़ाता है।

3. सुप्रीम कोर्ट के गोपनीयता सिद्धांत का उल्लंघन करता है

2017 के **केएस पुट्टास्वामी फैसले की** आवश्यकता है:

एक. **वैधता**

दो. **आवश्यक वस्तु**

तीन. **समानता**

अनिवार्य संचार साथी निर्देश आनुपातिकता परीक्षण में विफल रहता है क्योंकि:

- **कम दखल देने वाले विकल्प पहले से मौजूद** हैं (एसएमएस जांच, यूएसएसडी कोड, मौजूदा संचार साथी वेबसाइट)।
- गैर-हटाने योग्य स्थिति के साथ पूर्व-स्थापना अत्यधिक और अनावश्यक है।

4. उपयोगकर्ता अधिकारों और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव

- उपयोगकर्ता की स्वायत्तता को कमजोर करता है।
- प्रणालीगत कमजोरियां बनाता है - एक समझौता किया गया ऐप लाखों लोगों को उजागर कर सकता है।
- ऐप्पल जैसे वैश्विक निर्माता **कथित तौर पर अनुपालन से इनकार कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय** गोपनीयता अपेक्षाओं को उजागर करते हैं।

5. अति-विनियमन का जोखिम

जबकि साइबर अपराध एक वास्तविक खतरा है, ओएस स्तर पर सुरक्षा ऐप्स को अनिवार्य करना यह कर सकता है:

- भविष्य के मजबूर सॉफ़्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए एक मिसाल कायम करें,
- डिजिटल अधिकारों को कम करें,
- सरकार के प्रौद्योगिकी शासन में विश्वास को कम करना।

समाप्ति

जबकि साइबर अपराध जटिल हो गया है और मजबूत राज्य हस्तक्षेप की मांग करता है, एक पूर्व-स्थापित, गैर-हटाने योग्य संचार साथी ऐप को अनिवार्य करना **एक संकीर्ण समस्या के लिए एक व्यापक समाधान का प्रतिनिधित्व करता है**। यह निर्देश निजता के संवैधानिक अधिकार के साथ असंगत निगरानी बुनियादी ढांचे के निर्माण का जोखिम उठाता है और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित आनुपातिकता बेंचमार्क को विफल करता है। भारत को स्मार्ट, न्यूनतम दखल देने वाले साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है - न कि व्यापक नियंत्रण जो डिजिटल स्वतंत्रता और उपयोगकर्ता के विश्वास से समझौता करते हैं।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : भारत में निजता के अधिकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी फैसले (2017) में अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी।

निजता का अधिकार पूर्ण है और इसे किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।
गोपनीयता पर किसी भी प्रतिबंध को वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
एक। केवल एक
जन्म। केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं
उत्तर : b)

UPSC Mains Practice Question

सभी स्मार्टफोन पर संचार साथी ऐप को प्री-इंस्टालेशन अनिवार्य करना आनुपातिकता और निजता के अधिकार के सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पुट्टास्वामी (2017) के फैसले के आलोक में चर्चा करें।

Page 10 : GS 2 : IR

रूस-यूक्रेन युद्ध के लगभग चार साल बाद, कई राजनयिक प्रयासों के बावजूद शांति की संभावनाएं दूर हैं। 2022 में प्रारंभिक वार्ता ने युद्धविराम की संभावना का संकेत दिया था, लेकिन भू-राजनीतिक हितों, युद्ध के मैदान की गतिशीलता में बदलाव और बाहरी हस्तक्षेपों ने किसी भी सफलता को रोक दिया। आज, यूक्रेन को सैन्य असफलताओं, घरेलू दबाव और रणनीतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, खासकर **ट्रम्प प्रशासन** द्वारा आगे बढ़ाई **गई विवादास्पद 28-सूत्री शांति योजना** के उद्भव के बाद। यह योजना, जिसे रूसी हितों की ओर भारी झुकाव के रूप में माना जाता है, एक स्थिर समाधान प्राप्त करने की जटिलता को बढ़ाती है।

NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

□□□□□□ □□□□□□□

Why is there no peace in Ukraine?

While Ukraine faces the possibility of a prolonged war with Russia, a controversial 28-point peace plan from the Trump administration proposes recognition of Russian control over key territories. With pressure mounting on President Zelenskyy, the prospect of a ceasefire grows increasingly complicated amid military setbacks

WORLD INSIGHT

Stanly Johny

In late February 2022, days after Russia launched its invasion of Ukraine, Russian and Ukrainian officials met in Belarus, opening a diplomatic channel. Russian troops had advanced towards Kharkiv in the northeast and Kherson in the south, but if Moscow expected a quick victory, it was mistaken.

The talks that began in Belarus continued under Turkey's mediation, culminating in a meeting in Istanbul on March 29, 2022. Ahead of the talks, Turkish President Recep Tayyip Erdogan said Ukraine was ready to renounce NATO membership and recognise Russian as an official language. Soon after the Istanbul meeting, Russia announced that it would pull back troops from the Kyiv and Chernihiv fronts as a "diplomatic gesture". It later emerged that Russian and Ukrainian officials had tentatively agreed on the outlines of an interim settlement. According to a September 2022 essay in *Foreign Affairs* by Fiona Hill and Angela Stent, both former U.S. foreign service officials, it was decided that Russia would agree to withdraw to its pre-war position (meaning it would keep Crimea, annexed in 2014, and that pro-Russian rebels would control parts of Donetsk and Luhansk). In return, Ukraine would pledge not to seek NATO membership and instead receive security guarantees from a group of countries. According to Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, Moscow and Kyiv were ready to draft an agreement based on the Istanbul framework.

However, the Istanbul process collapsed. Western governments were hesitant to provide the security guarantees Ukraine demanded. According to Mr. Lavrov, then British Prime Minister Boris Johnson visited Kyiv in early April and "told them to continue to fight". Ukrainian President Volodimir Zelenskyy also appeared emboldened by Russia's withdrawal from the Kyiv area, which he interpreted as a sign of weakness. Naftali Bennett, the former Israeli Prime Minister who was also part of the negotiations, later said Russia and Ukraine had come close to making concessions that could have ended the conflict, but Mr. Johnson persuaded Mr. Zelenskyy to not back down. Ukraine chose to continue to fight, forcing Russian troops to withdraw from Khakiv and later Kherson. Russian President Vladimir Putin, in turn, doubled down – formally annexing four more Ukrainian territories and launching a partial mobilisation. The stage was set for a long war.

Trump's plan

Almost four years later, another peace plan, this time pushed by the Donald Trump administration, is being circulated among all parties. The 28-point plan appears even less favourable to Ukraine than the Istanbul framework. Kyiv now faces pressure on the frontline where Russian troops are making slow but steady gains; from the U.S., which wants Ukraine to make concessions; and at home where a corruption scandal has rocked the Zelenskyy regime.

According to Mr. Trump's draft plan, Crimea, Luhansk and Donetsk will be recognised "as de facto Russian". Russia controls the whole of Crimea and the whole of Luhansk, but only about 80% of Donetsk. As per the plan, Ukraine will have to withdraw troops from Donetsk. The line of contact in Kherson and Zaporizhzhia, two other provinces Russia has annexed and partly controls, will be frozen – which means Russia will keep the territories it has captured. Russia will relinquish the territories it has seized other than the five oblasts (say, in Kharkiv and Dnipropetrowski) in return for Ukraine's withdrawal from Donetsk. Ukraine will also have to limit the size of its armed forces to 6,00,000 personnel.

The most contentious point, besides territory, in the war was the role of NATO. Russia has consistently opposed Ukraine becoming a member of the trans-Atlantic nuclear alliance, which was founded during the Cold War. As of now, Ukraine doesn't have a pragmatic path towards NATO membership. The Trump administration has also repeatedly stated that Ukraine was unlikely to be a NATO member. While Kyiv had not given up its desire to join the bloc, now, according to the Trump plan, Ukraine should enshrine in its Constitution that it will not join NATO, and the alliance should include in its statutes that Ukraine will not be admitted in the future (but Ukraine can join the EU). "It is expected that Russia will not invade neighbouring countries and NATO will not expand further," reads another point in the plan. Russia and NATO will also initiate dialogue, under the mediation of the U.S., to resolve "all security issues".

If peace prevails, the U.S. promises to reintegrate Russia into the global economy. Sanctions could be lifted and the country could rejoin the G8 grouping (Russia was expelled after the annexation of Crimea), and enter a long-term economic cooperation agreement with the U.S. Moscow will have to enshrine in law its policy of non-aggression towards Europe and Ukraine. While the 28-point proposal says Ukraine will receive "reliable security guarantees", it doesn't offer details about the promise. The Trump administration has now circulated another draft agreement dealing only with the security part. The three-point plan, which needs the approval of Ukraine, Russia, the U.S., the EU and NATO, promises NATO-style security assurances to Ukraine for up to 10 years, which can be renewed by mutual agreement. A significant and sustained armed attack by Russia on Ukraine "shall be regarded as an attack threatening the peace and security of the transatlantic community," reads the document.

Facts on the ground

The Trump plan offers an initial outline to restart talks. While the proposal addresses both Ukraine's future security and Russia's stated concerns – including NATO's eastward expansion – it is widely seen as favouring Moscow. If implemented, Ukraine would have to cede territory, recognise Russian control of its regions and abandon NATO aspirations, while Russia would be reintegrated into the global political and economic mainstream. Mr. Zelenskyy's initial response was that Ukraine was being forced to choose between its dignity and a close partner (the U.S.). Nevertheless, Ukrainian officials held talks with European and U.S. officials to add their inputs to the Trump proposal.

While efforts to find a political solution continue, the facts on the ground have shifted significantly since the March 2022 Istanbul talks. At that time, Russia, whose initial attack had not gone according to plan, was on the back foot, and appeared willing to make concessions. But after suffering tactical setbacks in Kharkiv and Kherson, Russia regrouped and restructured its forces and shifted to a long-term war strategy. Over the past four years, Ukraine has received some of the West's most advanced defensive and offensive systems, including F-16s, Patriot missile defence systems, main battle tanks, armoured vehicles and medium to long range rockets, besides large quantities of ammunition. Yet, they couldn't stop Russia's grinding advances. On Monday, Russia's Defence Ministry announced that its troops captured Pokrovsk, a strategically important city in Donetsk, which had been under sustained Russian attack for over a year. The capture of Pokrovsk and Russian advances in Kupiansk (in Kharkiv) could clear the way for further Russian battlefield gains.

When Joe Biden was the U.S. President, Washington's policy was to support Ukraine "as long as it takes". There was a broad consensus between the U.S. and Europe that sustained military and economic assistance to Kyiv, combined with economic sanctions on Moscow, could eventually weaken Russia's war effort – or at least push Mr. Putin to seek a settlement that was not entirely favourable for Russia. But Ukraine's 2023 counteroffensive, aimed at recapturing lost territories, proved a decisive failure, effectively closing off the military option. The return of Mr. Trump to the White House in early 2025 meant that the trans-Atlantic consensus on Ukraine was broken. Mr. Trump saw the conflict as a lost war, and began shifting the burden of supporting Ukraine onto Europe. He believes that once the war is concluded, Washington and Moscow could reopen a new chapter in their historically troubled relationship.

Some in the U.S. strategic community also argue that Washington could attempt a 'Reverse Kissinger' – drawing Russia away from its deepening strategic partnership with China, the U.S's principal global rival.

Zelenskyy's dilemma

The Trump plan leaves Mr. Zelenskyy in a difficult position. The Ukrainian leader, whose term expired last year, continues to cling on to power under martial law. Last week, Mr. Zelenkyy's Chief of Staff Andriy Yermak resigned after a corruption scandal shook the regime. The economy is being propped up by aid from the West, and parts of the country are grappling with power outages as repeated Russian strikes target Ukraine's electricity grid. On the battlefield, the loss of Pokrovsk has marked a major setback.

Mr. Zelenskyy once insisted that peace would be possible only if Russia withdrew from all seized territories, including Crimea. Today, he is prepared to accept a ceasefire along the current frontline, which would leave more than 20% of pre-2014 Ukraine in Russian hands. In Istanbul, there was at least an outline for a possible agreement. That moment has passed.

Now, with the Trump plan, Ukraine finds itself in a much weaker position. It doesn't have a clear path towards military victory. Worse, it risks losing the support of Washington.

European countries, chiefly Germany, the U.K. and France, have pledged continued support. But those assurances carry limited weight if the U.S. exits the support architecture.

If Mr. Zelenskyy accepts the deal Mr. Trump is offering, it would amount to conceding victory to Russia. He could also face serious political consequences at home. If he rejects it, Ukraine risks losing more territory in a prolonged war.

A prolonged invasion

Russia's Defence Ministry has claimed that its troops have captured Pokrovsk, a strategically important city in Donetsk, which had been under sustained Russian attack for over a year. The capture of Pokrovsk could clear the way for further Russian battlefield gains

Russian control before February 24, 2022 | Front line on June 1, 2025 | Russian control and advances to December 1, 2025

SOURCE: Institute for the Study of War, Reuters

THE GIST

The talks that began in Belarus continued under Turkey's mediation, culminating in a meeting in Istanbul on March 29, 2022. It later emerged that Russian and Ukrainian officials had tentatively agreed on the outlines of an interim settlement.

However, the Istanbul process collapsed. Western governments were hesitant to provide the security guarantees Ukraine demanded. According to Mr. Lavrov, then British Prime Minister Boris Johnson visited Kyiv in early April and "told them to continue to fight".

The Trump plan offers an initial outline to restart talks. While the proposal addresses both Ukraine's future security and Russia's stated concerns — including NATO's eastward expansion — it is widely seen as favouring Moscow

पहले की शांति वार्ता क्यों विफल हो गई?

1. इस्तांबुल प्रक्रिया का पतन (मार्च 2022)

- युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद, रूस और यूक्रेन ने **बेलारूस और इस्तांबुल में वार्ता की**।
- एक अस्थायी समझौता सामने आया:

- रूस युद्ध-पूर्व पदों **पर वापस आ जाएगा** (क्रीमिया और डोनबास विद्रोही क्षेत्रों को बनाए रखेगा)।
- यूक्रेन सुरक्षा गारंटी के बदले में **नाटो की सदस्यता छोड़** देगा।

यह क्यों ढह गया?

- पश्चिमी देश यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के लिए तैयार नहीं थे।
- रिपोर्टों से पता चलता है कि बोरिस जॉनसन ने ज़ेलेंस्की से समझौता **करने के बजाय लड़ते रहने का आग्रह किया**।
- यूक्रेनी नेतृत्व ने कीव से रूस की वापसी को कमजोरी के संकेत के रूप में गलत समझा।
- परिणामस्वरूप, यूक्रेन ने सैन्य प्रतिरोध जारी रखने का फैसला किया, जिससे रूस को खार्किव और खेरसॉन से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।

परिणाम:
शीघ्र निपटान का मौका खो गया, जिससे संघर्ष लंबे समय तक युद्ध में बदल गया।

ट्रम्प प्रशासन की नई शांति योजना

विवादास्पद 28-सूत्री योजना के प्रमुख तत्व

एक. **रूसी नियंत्रण की मान्यता** :

- क्रीमिया
- लुगांस्क
- डोनेट्स्क (पूर्ण नियंत्रण, उन क्षेत्रों सहित जो अभी तक रूस के कब्जे में नहीं हैं)

दो. **खेरसॉन और ज़ापोरिज़्ज़िया में संघर्ष रेखाओं को फ्रीज** करना , जिससे रूस को कब्जे वाले क्षेत्र को बनाए रखने की अनुमति मिल गई।

तीन. **यूक्रेन को डोनेट्स्क से** सैनिकों को वापस लेना होगा।

चार. **यूक्रेनी सेना ने** 6,00,000 कर्मियों को सीमित कर दिया।

पाँच. **नाटो की सदस्यता को स्थायी रूप से खारिज कर** दिया गया:

- यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने के लिए संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए।

- नाटो को आधिकारिक तौर पर यूक्रेन को स्वीकार नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए।

छः. **रूस वैश्विक अर्थव्यवस्था में फिर से एकीकृत हो** गया:

- प्रतिबंध हटा दिए गए।
- G8 पर लौटें।
- अमेरिका के साथ आर्थिक सहयोग।

सात. एक अलग **सुरक्षा गारंटी योजना** यूक्रेन को 10 साल तक के लिए नाटो शैली का आश्वासन प्रदान करती है।

इसे कैसे देखा जाता है?

- इसे रूस के लिए अत्यधिक अनुकूल **माना जाता है**।
- यूक्रेन को इसकी आवश्यकता होगी:
  - बड़े क्षेत्रों को छोड़ दें,
  - नाटो को हमेशा के लिए छोड़ दो,
  - दीर्घकालिक सैन्य सीमाओं को स्वीकार करें।

युद्धक्षेत्र की वास्तविकताओं को बदलना

2022 के बाद से, युद्ध की तस्वीर बदल गई है:

यूक्रेन की गिरती स्थिति

- यूक्रेन का 2023 का जवाबी हमला विफल रहा।
- रूस ने डोनेट्स्क के एक रणनीतिक शहर पोक्रोव्स्क **पर कब्जा कर** लिया और कुपियान्स्क (खार्किव) में आगे बढ़ रहा है।
- पश्चिमी सैन्य सहायता धीमी हो गई है।
- लगातार रूसी हमले के तहत बिजली ग्रिड।
- आर्थिक अस्तित्व पश्चिमी निधियों से जुड़ा हुआ है।

रूस की मजबूत स्थिति

- शुरुआती असफलताओं के बाद, मास्को:
    - नए सैनिकों को जुटाया,
    - मजबूत रक्षात्मक रेखाएं,
    - एक स्थायी लंबे युद्ध की रणनीति में स्थानांतरित हो गया।
- रूस धीमी लेकिन स्थिर बढ़त **बना रहा है**।

शांति अभी भी मायावी क्यों है? - संरचनात्मक कारक

1. परस्पर विरोधी अंतिम लक्ष्य

- **यूक्रेन**: शुरू में क्रीमिया सहित पूरी **तरह से रूसी वापसी** की मांग की। अब मौजूदा तर्ज पर युद्धविराम स्वीकार करने को तैयार हैं - एक बड़ी चढ़ाई।
- **रूस**: यूक्रेनी तटस्थता, क्षेत्रीय रियायतें और नाटो को वापस लेना चाहता है।

2. बाहरी शक्तियों की भूमिका

- बिडेन के नेतृत्व में अमेरिका: यूक्रेन का समर्थन किया "जब तक यह लेता है"।
- ट्रम्प के तहत: युद्ध को **अजेय के रूप में देखता** है और जल्दी से बातचीत का सौदा चाहता है।
- यूरोप यूक्रेन का समर्थन करता है लेकिन अमेरिकी समर्थन के बिना रणनीतिक क्षमता का अभाव है।
- अमेरिकी रणनीतिक हलकों में कुछ लोग **"रिवर्स किसिंजर" चाहते हैं**: रूस को चीन से दूर खींचें।

3. घरेलू दबाव

- ज़ेलेंस्की का नेतृत्व तनाव में है:
    - उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है; वह मार्शल लॉ के तहत शासन करता है।
    - एक भ्रष्टाचार घोटाले के कारण उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया।
    - जनता की थकान और आर्थिक तनाव बढ़ रहा है।

4. जमे हुए कूटनीति

- 2022 के विपरीत, वर्तमान में कोई भी पक्ष बातचीत के माध्यम से किए गए समाधान को फायदेमंद नहीं मानता है:
    - रूस का मानना है कि समय उसकी सेना के पक्ष में है।
    - यूक्रेन को पश्चिमी समर्थन के बिना और अधिक खोने का डर है।

श्री ज़ेलेंस्की की रणनीतिक दुविधा

यूक्रेन अब एक कठिन चौराहे पर खड़ा है:

यदि वह ट्रम्प के सौदे को स्वीकार करते हैं:

- यह प्रभावी रूप से **रूस की जीत को स्वीकार करता है**।
- वह घर में राजनीतिक प्रतिक्रिया का जोखिम उठाते हैं।
- यूक्रेन अपने 20% से अधिक क्षेत्र को स्थायी रूप से खो देता है।

यदि वह सौदे को अस्वीकार करता है:

- अमेरिकी समर्थन खोने का जोखिम।
- लंबे समय तक युद्ध से अधिक क्षेत्रीय नुकसान हो सकता है।
- अकेले पश्चिमी (विशेषकर यूरोपीय) समर्थन पर्याप्त नहीं हो सकता है।

समाप्ति

यूक्रेन में शांति मायावी बनी हुई है क्योंकि **प्रमुख अभिनेताओं के सैन्य, राजनीतिक और राजनयिक प्रोत्साहन गलत हैं**। समझौते की शुरुआती संभावनाएं खो गईं, और विकसित युद्धक्षेत्र की वास्तविकता अब रूस के पक्ष में है। नई ट्रम्प-समर्थित शांति योजना मामलों को और जटिल बनाती है, जिससे यूक्रेन को क्षेत्रीय नुकसान और निरंतर संघर्ष के बीच एक अप्रिय विकल्प मिलता है। कमजोर होती पश्चिमी एकता और बढ़ती आंतरिक चुनौतियों के साथ, यूक्रेन को युद्ध शुरू होने के बाद से अपने सबसे कठिन रणनीतिक क्षणों में से एक का सामना करना पड़ रहा है। जब तक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य ढांचा नहीं उभरता है - जो रूस की सुरक्षा चिंताओं और यूक्रेन की संप्रभुता दोनों को संबोधित करता है - तब तक संघर्ष एक लंबे, पीसने वाले युद्ध के रूप में जारी रहने की संभावना है।

प्रश्न : रूस-यूक्रेन संघर्ष में एक स्थायी शांति समझौता अभी भी मायावी क्यों है? चर्चा करना। **(150 शब्द)**

Page : 08 : Editorial Analysis

A template for security cooperation in the Indian Ocean

Harsh V. Pant
is Vice-President, The Observer Research Foundation

Sayatan Haldar
is Associate Fellow, Maritime Studies, The Observer Research Foundation

There are encouraging signs that member-country engagement is deepening in the Colombo Security Conclave, but challenges remain

On November 20, 2025, India hosted the 7th National Security Advisor-level summit of the Colombo Security Conclave (CSC). India's National Security Adviser, Ajit Doval, hosted his counterparts from other member-countries, Sri Lanka, the Maldives, Mauritius and Bangladesh, while counterparts from Seychelles and Malaysia were observer state and guest, respectively. The CSC has sought to position itself as a critical forum to promote and foster cooperation in the domain of security in the Indian Ocean region.

Initiated as a trilateral grouping between India, Sri Lanka and Maldives in 2011, the group lost steam in light of the political transition in the Maldives and Sri Lanka, and lack of convergence among the member-states to identify priorities in security cooperation in the Indian Ocean. The group reconvened its engagement under the aegis of the CSC in 2020, a proposed framework to further cooperation in maritime security, counter-terrorism, trafficking and organised crime and cybersecurity. Since then, the group has remained steady in not just maintaining momentum among its member-states but also inducting countries. In 2022, Mauritius joined as a full member, while in 2024, the group saw the admission of Bangladesh.

A region witnessing shifts

For India, the summit, in 2025, comes at a pivotal moment. Frameworks of cooperation in the maritime domain, in the broader Indo-Pacific, and indeed in the Indian Ocean appear to be undergoing a crucial shift. Given the focus of the CSC on non-traditional issues of maritime security, it is vital to bolster cooperation in mitigating the looming challenges. While the Indian Ocean maritime security architecture remains fragmented due to the lack of any singular institutional framework, groups such as the CSC must remain committed to enhancing cooperation in this regard.

The issue of development

Importantly, for the wider Indian Ocean littoral world, and especially the members of the CSC, maritime security challenges are often coupled with their developmental priorities.

Given the extent of dependency these countries have on the oceans for their economic progress, securing challenges emanating from the maritime domain is crucial. In many ways, maritime security challenges are deeply intertwined with the lives and livelihoods of not just the littoral communities in these countries but also appear to unlock new opportunities for their national economies in today's era of sea-borne globalisation.

This year's summit has been crucial in many ways. First, the group saw further expansion by way of accession of Seychelles as a full-member into the forum. This signals a deep commitment among countries in the region to harness cooperation within the mandate of the CSC. Second, for India, the CSC also marks a new step in further deepening engagement with its maritime neighbours, amidst an increasingly volatile geopolitical and security shift that appears to be underway in the region in lieu of China's growing presence and influence.

Third, the summit further underscores the growing vitality of the security dimension in enhancing cooperation to boost regional cooperation in the Indian Ocean.

Fourth, the inclusion of Malaysia in this year's summit as a guest participant may pave the way for further expansion of the group.

Viewing the China factor

However, as the CSC envisages its expansion and broadening the contours of its agenda, some key challenges appear to be looming. First, for India, a key maritime security priority is anchored in the nature and extent of the Chinese presence in the Indian Ocean. On the other hand, the other member countries of the CSC appear to not view the Chinese presence in the Indian Ocean as a major security challenge given their dependence on Beijing as a key developmental partner. Therefore, a careful balance needs to be achieved by India to address the question of growing Chinese presence in the Indian Ocean.

Second, the CSC must direct efforts to strengthen an institutional framework. At present, the group operates at a National Security Adviser-level structure. With growing synergies among its member-countries, the group must seek to institutionalise cooperation such that it remains consistent in aligning policies with actionable pathways of cooperation.

Third, domestic uncertainties in countries such as Bangladesh, and the ensuing impact on how Dhaka continues to engage with India and the other member-countries may run the risk of uncertainty over the group's resilience.

Given this context, the CSC has made significant advances in heralding a new framework of cooperation in a region that suffers from a deep lack of cohesion and convergence among countries on issues of security. Efforts to imagine the way ahead must remain anchored in the need to foster institutional resilience and cohesion among its member-countries.

GS-2: IR

UPSC Mains Practice Question : कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) हिंद महासागर में सहकारी सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचे के रूप में उभर रहा है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता सदस्य देशों के बीच अलग-अलग रणनीतिक प्राथमिकताओं से बाधित है। चर्चा करना। **(250 शब्द)**

संदर्भ:

नवंबर 2025 में भारत द्वारा आयोजित कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक, भारत की समुद्री कूटनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण है। जैसे-जैसे हिंद महासागर में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है - विशेष रूप से चीन के बढ़ते पदचिह्न के साथ - सीएससी गैर-पारंपरिक खतरों पर केंद्रित क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के लिए एक प्रमुख लघुपक्षीय मंच के रूप में उभर रहा है।

पृष्ठभूमि

- मूल रूप से 2011 में त्रिपक्षीय (भारत-श्रीलंका-मालदीव) के रूप में गठित।
- 2020 में सीएससी के रूप में पुनर्जीवित किया गया, इसके दायरे का विस्तार किया गया:
    - समुद्री सुरक्षा
    - आतंकवाद का मुकाबला
    - तस्करी और संगठित अपराध
    - साइबर सुरक्षा
- मॉरीशस (2022) और बांग्लादेश (2024) पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए।
- सेशेल्स (2025) ने हाल ही में पूर्ण सदस्यता प्राप्त की है।
- मलेशिया ने इस वर्ष अतिथि-देश के रूप में भाग लिया, जो भविष्य के विस्तार का संकेत देता है।

2025 शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं

एक. सदस्यता का विस्तार - सेशेल्स एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होता है, जो क्षेत्रीय विश्वास का संकेत देता है।

दो. भारत ने समुद्री जुड़ाव को गहरा किया - यह भारत के सागर विजन और इंडो-पैसिफिक रणनीति के अनुरूप है।

तीन. क्षेत्रीय अस्थिरता और चीन की बढ़ती उपस्थिति के कारण सुरक्षा सहयोग का बढ़ता महत्व।

चार. मलेशिया की भागीदारी से और विस्तार की संभावना।

हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सीएससी क्यों मायने रखता है

1. खंडित समुद्री सुरक्षा वास्तुकला

हिंद महासागर में एक भी एकीकृत ढांचे का अभाव है। सीएससी इस अंतर को बढ़ावा देकर भरता है:

- जानकारी साझा करना
- क्षमता निर्माण
- समुद्री डोमेन जागरूकता

- एंटी-पाइरेसी, एंटी-ट्रैफिकिंग ऑपरेशन

2. सुरक्षा और विकास के बीच अंतर्संबंध

छोटे तटीय राज्यों के लिए:

- समुद्री संसाधन उनकी अर्थव्यवस्थाओं को चलाते हैं।
- नीली अर्थव्यवस्था, मत्स्य पालन, पर्यटन और व्यापार सुरक्षित समुद्रों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार, सीएससी सुरक्षा और विकासात्मक प्राथमिकताओं दोनों का समर्थन करता है।

3. भारत की पड़ोस-प्रथम नीति के लिए एक मंच

सीएससी मजबूत करता है:

- क्षेत्रीय ट्रस्ट
- समुद्री मुद्दों पर नीति संरेखण
- हिंद महासागर में भारत की नेतृत्व भूमिका

प्रमुख चुनौतियाँ

1. चीन की भूमिका पर मतभेद

- भारत चीन के सैन्य और रणनीतिक पदचिह्न को एक बड़े सुरक्षा खतरे के रूप में देखता है।
- अन्य सीएससी सदस्य इसके लिए चीन पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं:
  - अवसरंचना
  - निवेश
  - व्यापारइस प्रकार, वे चीन को सुरक्षा चुनौती के रूप में लेबल करने में संकोच कर रहे हैं। विकास की जरूरतों और सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

2. मजबूत संस्थागतकरण का अभाव

- सीएससी वर्तमान में मुख्य रूप से एनएसए-स्तर पर कार्य करता है
- की अनुपस्थिति:
  - सचिवालय
  - कानूनी ढांचा
  - स्थायी समन्वय तंत्र यह दीर्घकालिक नीति निरंतरता को सीमित करता है।

3. घरेलू राजनीतिक अनिश्चितताएं

- राजनीतिक बदलाव, विशेष रूप से बांग्लादेश में, सीएससी लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रभावित कर सकते हैं।
- छोटे द्वीप राज्यों को लगातार नेतृत्व परिवर्तन का सामना करना पड़ता है जो आम सहमति को बाधित कर सकता है।

आगे की राह

एक. संस्थागत तंत्र को मजबूत करना

- स्थायी सचिवालय
- नियमित कार्य-स्तरीय बैठकें
- साइबर, समुद्री और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों के लिए संयुक्त कार्य बल

दो. चीन से संबंधित संवेदनशीलता को संतुलित करें

- गैर-पारंपरिक चुनौतियों (समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ना, तस्करी) पर ध्यान केंद्रित करें
- विकासोन्मुखी समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना

तीन. क्षमता निर्माण को बढ़ावा दें

- प्रशिक्षण, गश्ती जहाज, रडार स्टेशन, समुद्री डोमेन जागरूकता
- संयुक्त अभ्यास और प्रौद्योगिकी साझाकरण

चार. सावधानी से साझेदारी का विस्तार करें

- मुख्य एजेंडे को कमजोर किए बिना पर्यवेक्षक और अतिथि राज्यों को शामिल करें

समाप्ति

सीएससी एक जटिल और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर में लघुपक्षीय सुरक्षा सहयोग के लिए एक आशाजनक क्षेत्रीय मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, विशेष रूप से चीन का बढ़ता प्रभाव, महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करता है, संस्थागत मजबूती और निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता सीएससी को क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों का समर्थन करने वाले एक लचीले तंत्र में बदल सकती है। भारत के लिए, सीएससी एक सुरक्षित, स्थिर और सहकारी हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करने की अपनी महत्वाकांक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

Follow More

- **Phone Number : - 9999154587**
- **Email : - k.nitinca@gmail.com**
- **Website : - https://nitinsirclasses.com/**
- **Youtube : -https://youtube.com/@nitinsirclasses8314?si=a7Wf6zaTC5Px08Nf**
- **Instagram :- https://www.instagram.com/k.nitinca?igsh=MTVxeXgxNGJyajN3aw==**
- **Facebook : - https://www.facebook.com/share/19JbpGvTgM/?mibextid=qi2Omg**
- **Telegram : - https://t.me/+ebUFssPR83NhNmJl**